जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग

प्रसंग

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने नए केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से समायोजित करने के लिए जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के गठन की चुनौती को खारिज कर दिया।

मुख्य बिंदु :-

याचिकाकर्ता का तर्क: दायर की गई याचिका केंद्र द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना को चुनौती देने तक सीमित थी-

- मार्च 2020 में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग की स्थापना।
- मार्च 2021 में केवल जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन कराने के उद्देश्य से अपना कार्यकाल का बढ़ना।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी :

- संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 संसद को नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने में सक्षम बनाते हैं।
- तदनुसार, दो नए यूटी बनाए गए हैं।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जिसने दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया, परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन की भूमिका प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया कानून हमेशा परिसीमन आयोग के माध्यम से नवगठित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के लिए प्रदान कर सकता है।
- 6 मार्च, 2020 के आदेश के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना से जुड़ी कोई अवैधता नहीं है।

परिसीमन के बारे में

- परिसीमन एक विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण है।
- यह एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाता है।
- परिसीमन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए राज्य विधानसभा या लोकसभा में निर्दिष्ट संख्या में सीटों को आरक्षित करने के लिए भी उत्तरदायी है।

परिसीमन आयोग के बारे में

संवैधानिक प्रावधान :

- अनुच्छेद 82 : संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है।
- अनुच्छेद 170: प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को भी परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है।
- सदस्य: सेवारत या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या संबंधित राज्यों के सीईसी और चुनाव आयुक्त द्वारा नामित एक चुनाव आयुक्त।
- राष्ट्रीय स्तर पर अब तक (1952, 1963, 1972 और 2002) चार परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है।

जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग

- परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2021 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई ने की।
- इसके सहयोगी सदस्यों के रूप में जम्मू-कश्मीर के पांच सांसद हैं।
- 2019 तक, जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास देश के बाकी हिस्सों से अलग किया जाता था।जहाँ जम्मू और कश्मीर में लोकसभा सीटों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित था, राज्य की विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू और कश्मीर संविधान द्वारा शासित था।
- नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार होंगी।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

माइक्रोएलईडी डिस्प्ले

प्रसंग

Apple की माइक्रोएलईडी डिस्प्ले तकनीक में बदलाव कथित तौर पर प्रक्रियाधीन है। इसे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

माइक्रोएलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में

- माइक्रोएलईडी तकनीक का आधार नीलम है।
- नीलम सदैव चमक सकता है।
- एक माइक्रोएलईडी स्क्रीन अत्यंत छोटी तथा तीव्र रौशनी से युक्त होती है।
- एक माइक्रोएलईडी स्क्रीन में तस्वीर कई अलग-अलग प्रकाश उत्सर्जक डायोड द्वारा उत्पन्न होती है।
- एक माइक्रोएलईडी एक सेंटीमीटर बाल को 200 छोटे टुकड़ों में काटने जितना छोटा है।
- इनमें से प्रत्येक माइक्रोएलईडी अर्धचालक हैं जो विद्युत संकेत प्राप्त करते हैं।
- ये माइक्रोएलईडी एकत्रित होकर मॉड्यूल का निर्माण करते हैं।
- ▪ स्क्रीन बनाने के लिए कई मॉड्यूल को जोड़ा जाता है।

लाभ

- माइक्रोएलईडी डिस्प्ले अधिक चमकीले होते हैं, इनमें बेहतर कलर रिप्रोडक्शन होता है और बेहतर व्यूइंग एंगल प्रदान करते हैं।
- वे छवियों को ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे कि वे डिवाइस के ग्लास के ऊपर पेंट किए गए हों। यह फीचर अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है।
- माइक्रोएलईडी में असीमित मापनीयता होती है, क्योंकि वे रिज़ॉल्यूशन-मुक्त, बेज़ेल-मुक्त, अनुपात-मुक्त और यहां तक कि आकार-मुक्त होते हैं।
- व्यावहारिक उपयोग के लिए स्क्रीन को किसी भी रूप में स्वतंत्र रूप से आकार दिया जा सकता है।
- ▪ माइक्रोएलईडी पारंपरिक डिस्प्ले के समान बैकलाइटिंग या कलर फिल्टर की आवश्यकता के बिना स्वयं ही लाल, हरे और नीले रंग का उत्पादन करते हैं।

बीमारू राज्य

प्रसंग

उत्तर प्रदेश सरकार के दो दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन, प्रधान मंत्री ने पूर्व में राज्य का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त 'बीमारू' के टैग को याद किया।

मुख्य विशेषताएं:

- प्रधान मंत्री ने बीमारू टैग का प्रयोग पहले यूपी इन्वेस्टर समिट तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर राजस्थान में किया।
- ध्यातव्य है कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को संदर्भित करने के लिए अक्सर बीमारू परिवर्णी शब्द का उपयोग पिछले कुछ दशकों में किया गया है, आमतौर पर इसका मतलब यह है कि वे आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य के मामले में पिछड़ गए हैं।

बीमारू राज्य का क्या अर्थ है, यह शब्द किसने गढ़ा था?

- आशीष बोस, दिवंगत जनसांख्यिकीविद् (जो जनसंख्या और इसके भीतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं), ने इस शब्द को तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी को प्रस्तुत एक पत्र में गढ़ा था।
- उस समय, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य अलग-अलग राज्य नहीं थे और समूह का हिस्सा थे। हिंदी में बीमारू का अर्थ है "बीमार"।
- बोस ने 1985 में भारत की जनसांख्यिकीय समस्या को इंगित करने के लिए इस शब्द को गढ़ा था, जब उन्हें भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में तत्कालीन प्रधान मंत्री को जानकारी देने के लिए कहा गया था।

जनसंख्या वृद्धि में बीमारू राज्यों की क्या भूमिका है?

- "पूर्ववर्ती बीमारू राज्य, जो 2001 में भारत की कुल जनसंख्या का 41% था, 2026 में 43.5% हो जाएगा। यह भी दर्शाता है कि 2001-26 के दौरान भारत की जनसंख्या में पूर्ण वृद्धि में बीमारू राज्यों का हिस्सा होगा 50.4% का क्रम जबकि दक्षिण का हिस्सा केवल 12.6% होगा।।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग की 2020 की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट है, ने कहा कि बीमारू राज्य (तीन नए बनाए गए राज्यों को छोड़कर) 2011 और 2036 के बीच भारत में जनसंख्या वृद्धि का 49.1% योगदान करेंगे।
- भारतीय राज्यों में जनसंख्या भी परिसीमन प्रक्रिया या संसद में उन्हें आवंटित सीटों की संख्या निर्धारित करती है।
- दक्षिणी राज्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन और राज्यों को धन का हस्तांतरण उनके लिए अनुचित है।

- बोस ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से, ये चार राज्य अपनी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के साथ देश में कहीं और किए गए लाभ को ऑफसेट करने की संभावना रखते हैं।
- एक "स्थिर जनसंख्या" तक पहुँचने का राष्ट्रीय लक्ष्य, (जिसका अर्थ है कि जहाँ 2.1 की कुल प्रजनन दर (TFR) प्राप्त की गई थी) को इन राज्यों के कारण प्राप्त करना कठिन है।
- टीएफआर का अर्थ है कि प्रत्येक महिला अपने जीवनकाल में औसतन कितने बच्चे पैदा करती है।

समय के साथ बीमारू का उपयोग कैसे किया गया है?

- इन राज्यों में सत्ता में पार्टियों की आलोचना करने और कुछ प्रगति हासिल करने में सफलता दिखाने के लिए बीमारू टैग का उपयोग किया गया है।
- कभी-कभी बीमारू के रूप में ओडिशा को भी समूह में शामिल किया जाता है, हालांकि यह जनसंख्या के मामले में इतना बड़ा राज्य नहीं है।
- 2001 में इन पांच राज्यों के लिए एक अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) की स्थापना की गई थी।

संक्षिप्त सुर्खियां

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)

प्रसंग

31.01.2023 तक, उड़ान योजना के तहत 2017 के बाद से 9 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित कुल 73 अप्रयुक्त / कम उपयोग वाले हवाई अड्डों का संचालन किया गया है।

उड़ान योजना के बारे में

- UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) सरकार द्वारा देश के कम उपयोगी और अनएक्सप्लोरड हवाई अड्डों को जोड़ने की एक पहल है।
- इसे 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में लॉन्च किया गया था।
- इस योजना में निम्नलिखित को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है-
  - कम सेवा वाले हवाईअड्डे- वे हवाईअड्डे जिनके पास एक दिन में एक उड़ान से अधिक नहीं है।
  - बिना सेवा वाले हवाईअड्डे- वे जहां कोई परिचालन नहीं है।
- उड़ान एक बाजार संचालित योजना है:
  - इच्छुक एयरलाइनें विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर उड़ान के तहत बोली लगाते समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।
  - इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकारो द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जा रहा है। ।
  - यह योजना 10 साल तक चलेगी और उसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है।

महत्व:

- उड़ान योजना ने पूरे भारत में पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और द्वीपों सहित कई क्षेत्रों को अत्यधिक लाभान्वित किया है।
- इसने वायुयात्रा के व्यय को भी कम किया है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ)

प्रसंग

सरकारी एजेंसियों ने इस वर्ष के अंत में अपेक्षित पारस्परिक मूल्यांकन के चौथे दौर में भारत के आने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के आकलन को ध्यान में रखते हुए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण ढांचे को और मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाई है।

एफएटीएफ के बारे में

- FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मनी

लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए की गई थी।

- 2001 में आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए इसके शासनादेश का विस्तार किया गया था।
- उद्देश्य: धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता से संबंधित खतरों का मुकाबला करना।

सदस्य:

- एफएटीएफ में वर्तमान में दो क्षेत्रीय संगठनों -यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद सहित 39 सदस्य हैं।
- भारत ,एफएटीएफ परामर्श और उसके एशिया प्रशांत समूह का सदस्य है।

• **सचिवालय**- पेरिस।

• ग्रे लिस्ट में शामिल होने पर हो सकता है निम्नलिखित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है -

- आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी से आर्थिक प्रतिबंध।
- आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी और अन्य देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी
- अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार।

मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस (MIIRA)

प्रसंग

अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण को कृषि में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ, भारत बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल MIIRA के लॉन्च का प्रस्ताव करने की योजना बना रहा है।

मीरा के बारे में

- "MIIRA" का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करना होगा।
- यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने और भारत को बाजरा के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की केंद्र की योजना के अनुरूप है।
- उद्देश्य: बाजरा के पोषण मूल्य और जलवायु अनुकूल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए MIIRA लॉन्च किया जाएगा।
- MIIRA का उद्देश्य बाजरा फसलों पर अनुसंधान का समर्थन करते हुए दुनिया भर में बाजरा अनुसंधान संगठनों को जोड़ना है।
- यह शोधकर्ताओं को जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा।
- योजना जागरूकता बढ़ाकर बाजरे की उपभोग को बढ़ावा देने की भी है।

सचिवालय: दिल्ली

साइड नोट:

- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में विभिन्न प्रकार के बाजरा का वर्णन किया है
- भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

सरोजिनी नायडू

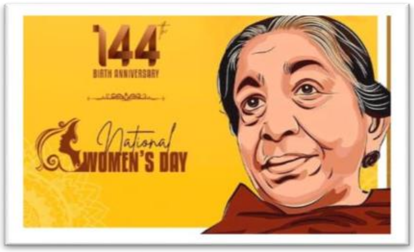

प्रसंग

भारत ने 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया।

सरोजिनी नायडू के बारे में:

- सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
- 1947 से 1949 तक, नायडू ने संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) के पहले राज्यपाल के रूप में कार्य किया, और उन्होंने भारतीय संविधान के विकास में भी सहायता की
- ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनकी सेवा के लिए सरोजिनी नायडू को 'कैसर-ए-हिंद' से सम्मानित किया।
- सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन का एक अनिवार्य हिस्सा थीं।
- वह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन का भी हिस्सा थीं।

सीबीआरएम हथियार

प्रसंग

तारकश नामक एक चल रहे भारत-अमेरिका संयुक्त अभ्यास में पहली बार "रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) शस्त्रों को सम्मिलित किया गया।

सीबीआरएन हथियार क्या हैं?

- सीबीआरएन हथियारों में बड़े पैमाने पर हताहत होने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने की क्षमता होती है और इसलिए, सामूहिक विनाश के हथियारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- रासायनिक हथियारों में मस्टर्ड गैस (श्वसन पथ, त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचाता है) और तंत्रिका एजेंट (पीड़ित तेजी से बेहोश हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, और मर सकते हैं) शामिल हैं।
- जैविक एजेंट जैसे एंथ्रेक्स बुखार, अस्वस्थता, खांसी और सदमे का कारण बनता है। इसमें मृत्यु 36 घंटों के भीतर हो सकती है, बोटुलिनम विष (श्वसन की मांसपेशियों के पक्षाघात की ओर जाता है) और प्लेग जैव रासायनिक हथियारों के कुछ उदाहरण हैं।
- रेडियोलॉजिकल हथियारों में हथियारयुक्त रेडियोधर्मी अपशिष्ट और बमों के साथ-साथ परमाणु हथियार भी शामिल हैं।
- तरकश राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस का एक संयुक्त अभ्यास है।

एयरो इंडिया 2023

प्रसंग

एयरो इंडिया शो बेंगलुरु के येलहंका में वायु सेना स्टेशन में शुरू किया गया ; प्रधानमंत्री ने द्विवार्षिक शो के 14वें संस्करण में इसका उद्घाटन किया।

एयरो इंडिया शो के बारे में

- रक्षा मंत्रालय, एयरो के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से भारत में इस साल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा आयोजन किया जा रहा है।
- "इस कार्यक्रम का उद्देश्य हल्के लड़ाकू विमान (LCA)-तेजस, HTT-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकाप्टर (LUH), हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर (LCH) और उन्नत हल्के हेलीकाप्टर (ALH) जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफार्मों के निर्यात को बढ़ावा देना है।
- यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में घरेलू एमएसएमई और स्टार्ट-अप को एकीकृत करेगा और सह-विकास और सह-

	उत्पादन के लिए साझेदारी सहित विदेशी निवेश आकर्षित करेगा। • मित्र देशों के रक्षा मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे, जिसका आयोजन 'रक्षा में संवर्धित संलग्नताओं के माध्यम से साझा समृद्धि (स्पीड)' विषय पर आयोजित किया गया है। • विभिन्न भारतीय और विदेशी रक्षा कंपनियों और संगठनों के बीच साझेदारी के लिए 75,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ लगभग 251 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।
सूर्य का उत्तरी ध्रुव	**प्रसंग** हाल ही में, सूर्य ने अपने उत्तरी ध्रुव के पास बड़ी प्रमुखता से कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। **मुख्य विशेषताएं:** • उत्तरी क्षेत्र की सामग्री मुख्य फिलामेंट से अलग हो गई और अब सूर्य के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल ध्रुवीय भंवर में घूम रही है। **घटना के मायने?** • स्पेस डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकार की सौर गतिविधि हर 11 साल में 55° अक्षांश पर यानी प्रत्येक सौर चक्र की अवधि में देखी गई है। • इस चक्र में सौर चुंबकीय क्षेत्र स्वयं को उलट देता है। जबकि वैज्ञानिक सौर गतिविधि के उतार-चढ़ाव से परिचित हैं, इस विशेष अक्षांश के पास ऐसी ज्वालाएँ क्यों फूटती हैं, हर चक्र अनुत्तरित रहता है। • • इस विशेष घटना में, वैज्ञानिकों ने एक फिलामेंट को पहली बार एक ध्रुवीय बवंडर के रूप में देखा।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare